संख्या-5 /2018/2964/बावन-1-2017-38(एम०एस०डी०पी०)/17

प्रेषक,

डा०पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 05 जनवरी, 2018

विषय -मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-शाहजहांपुर के वि०ख०-खुटार के ग्राम- चमराभोजी, नगरा एवं अण्डहा में स्वीकृत 03 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- एम०एस०डी०पी०/13/310/2017-एम०एस०डी०पी०-एम०ओ०एम०ए०, दिनांक 27.09.2017 से जनपद-शाहजहांपुर की उक्त योजना के लिए कुल अनुमोदित लागत रू० 22.50 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ०प्र०विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, (पैकफेड) लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 13.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 06,75,000/-(रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 04,50,000/-(रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 11,25,000/- (रू0 ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 1658.89 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

के० 60 : रा० 40										(रू0 लाख में)
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	वर्तमान में अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शाहजहांपुर	वि०ख०-खुटार के ग्राम- चमराभोजी, नगरा एवं अण्डहा में आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	03	7.50	13.50	9.00	22.50	6.75	4.50	11.25
		योग	03	7.50	13.50	9.00	22.50	6.75	4.50	11.25

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो,प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाईड लाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा।

3- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था उ०प्र०विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि०, (पैकफेड) लखनऊ नामित है। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अवमुक्त धनराशि से 06 माह में पूरा कर लिया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। इस संबंध में सम्पादित त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

4- धनराशि योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर प्रश्नगत आंगनवाड़ी योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/बावन-1-2009-1(1)/2009, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मात्रात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

8- आहरित धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

09- आहरण एवं वितरण आधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

10- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यवाही संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय । कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

11- अवमुक्त धनराशि को व्यय किये जाने के उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण-कार्यों के फोटोग्राफ्स की दो-दो प्रतियां जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

12- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के लिये अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा तथा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० के माध्यम से राजकोष मे जमा कराया जायेगा ।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनाया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय-स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

14- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी सस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी ।

15- जिलाधिकारी द्वारा उक्त निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता व निर्माण कार्य उपयुक्त स्थान पर ही हो रहा है, के सम्बन्ध में आश्वस्त हो लिया जायेगा तथा प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष संतोषजनक व गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में पूर्णत: पुष्टि कर ली जायेगी ।

16- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

17- प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

18- आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी ।

19- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

20- शासनादेश दिनांक 03 अगस्त 2017 एवं 26-8-2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

21- लेबरसेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

22- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1094 /दस-2017, दिनांक 04.01.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा० पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

संख्या- (1)/बावन-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आंगनवाड़ी केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने तथा निर्माण के पश्चात स्टाफ आदि की व्यवस्था कर क्रियाशील कराने का कष्ट करें।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहांपुर को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले 03 आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि० (पैकफेड), लखन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले वि०ख०-खुटार के ग्राम-चमराभोजी, नगरा एवं अण्डहा में स्वीकृत 03 आंगनवाड़ी केन्द्रों का गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in